बंद शुगर मिलों को चालू करने में जुटी महाराष्ट्र सरकार

[जयश्री भोसले | पुणे]

भारत में 2017-18 सीजन के दौरान चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन के अपने पहले के अनुमान को रिवाइज करके 13 पर्सेंट बढ़ाकर 2.95 करोड़ टन कर दिया है। पिछला रिकॉर्ड 2014-15 के सीजन का था, जब देश में 2.84 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। हाल में ISMA ने जनवरी में जारी किए गए अपने दूसरे पूर्व अनुमान में 2017-18 के दौरान चीनी उत्पादन 2.61 करोड़ टन रहने की उम्मीद जताई थी। शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा कि गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन 60 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 100 टन प्रति हेक्टेयर और कर्नाटक में 91 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है। 28 फरवरी 2018 तक शुगर प्रॉडक्शन 2.3 करोड़ टन था।

ISMA ने एक बयान में कहा, '479 चीनी मिलें अभी भी गन्ने की पेराई कर रही हैं। दो से ज्यादा राज्यों में अनुमान से अधिक पैदावार की सूचना मिली है। इन सब बातों पर विचार करके ISMA ने अपने चीनी उत्पादन के अनुमान को रिवाइज करते हुए इसे मौजूदा सत्र के लिए बढ़ाकर 295 लाख टन कर दिया है।' रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 105.13 लाख टन, महाराष्ट्र में 101.3 लाख टन और कर्नाटक में 35.45 लाख शुगर प्रॉडक्शन की उम्मीद है।

2018-19 में गन्ने की रिकॉर्ड बुआई के अनुमान को देखते हुए सरकार उठा रही है कदम

चूंकि, अगले साल भी गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार राज्य में बंद पड़ी मिलों को शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, जिससे गन्ने की पेराई में संकट का सामना न करना पड़े। इस प्रस्ताव के पहले चरण में सरकार ने 8 चीनी मिलों की पहचान की है। इन्हें फिर से चालू करने के लिए करीब 307.8 करोड़ रुपये की मदद की जरूरत है। प्रदेश में कुल 175 को-आपरेटिव चीनी मिले थीं, जिनमें से सिर्फ 93 चल रही हैं। बाकी बची हुई में से 33 मिलों का सारफेसी एक्ट के तहत अधिग्रहण हो गया, 6 बेची जा चुकी हैं, 3 को प्राइवेट शुगर मिल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और बची हुई 40 मिलें अलग-अलग वजहों से बंद पड़ी हैं।

अभी तक मौजूदा गन्ने का पेराई सत्र खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चीनी उद्योग के दिग्गज और राज्य सरकार 2018-19 सीजन के लिए गन्ने की रिकॉर्ड बुआई के अनुमान को लेकर चिंतित हो रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने सितंबर में 40 बंद पड़ी मिलों की स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और फिर से शुरू करने के लिए उन्हें वरीयता के आधार में तीन ग्रुप में बांटने के लिए कहा था। योजना के पहले चरण में कमेटी ने 8 बंद पड़ी शुगर को-आपरेटिव को फिर से चालू करने की सिफारिश की। इनमें से 5 मिलें बिकने की स्थिति में पहुंच गई हैं। उन्हें उबारने के लिए 307.79 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की जरूरत है।

The Economic Times
9/3/18